हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com

अपना राजकाज

जमशेदपुर
शुक्रवार
10 जुलाई 2026

झारखंड में लंबे साथ के लिए देश-दुनिया ने बढ़ाया निवेश का हाथ

झारखंड सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के दूसरे दिन गुरुवार को बिजनेस-टू-गवर्नमेंट संवाद हुआ। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश-विदेश के प्रमुख उद्योग संगठनों, वैश्विक निवेशकों तथा कॉरपोरेट प्रतिनिधिमंडलों के साथ कई बैठकें कीं। इनमें पर्यटन, निर्माण, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आईटी जैसे क्षेत्रों में झारखंड में लंबे साथ के लिए देश-दुनिया की कंपनियों ने निवेश का हाथ बढ़ाया।

सिंगापुर

भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग वी कुएन व उनकी टीम ने झारखंड से दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने में रुचि दिखाई। निवेश, विश्वस्तरीय स्किल सेंटर एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, सिंगापुर के व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉडल को अपनाने, उद्योग एवं कौशल मानचित्रण, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्पताल संरचना और प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साझेदारी की संभावनाओं पर भी विचार साझा किए।

सीआईआई

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में सौर एवं पवन ऊर्जा, स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसमिशन अवसंरचना, ग्रिड आधुनिकीकरण, सोलर सेल एवं मॉड्यूल निर्माण तथा डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में निवेश संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों की सराहना करते हुए राज्य में हरित ऊर्जा आधारित औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निरंतर संवाद एवं सहयोग का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली में गुरुवार को स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में सीएम हेमंत प्रसन्न मुद्रा में।

हीरो व एवन साइकिल्स

मुख्यमंत्री ने हीरो साइकिल्स एवं एवन साइकिल्स के प्रतिनिधियों से झारखंड में साइकिल एवं ई-साइकिल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना पर चर्चा की। कहा कि राज्य सरकार उद्योग-अनुकूल नीतियों, भूमि, इस्पात आधारित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र, बेहतर लॉजिस्टिक्स तथा कुशल मानव संसाधन देगी। बैठक में ₹500 से ₹1,000 करोड़ तक के संभावित निवेश से समेकित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।

गोल्फ कोर्स व पर्यटन केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव

बैठक में फिक्की टूरिज्म फेडरेशन ने रांची में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला गोल्फ कोर्स एवं गोल्फ पर्यटन केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आतिथ्य एवं रियल एस्टेट क्षेत्र को नई गति मिलेगी। रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा झारखंड राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त रूप से उभरेगा।

फिक्की » फिक्की के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड को प्रकृति पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग, स्पोर्ट्स टूरिज्म तथा एमआईसीई पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए पर्यटन अवसंरचना, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्थानीय पर्यटक गाइड, आतिथ्य क्षेत्र में सुधार तथा बेहतर संपर्क व्यवस्था विकसित करने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेकमाइट्रिप » मेकमाइट्रिप के प्रतिनिधियों ने भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं व्यापक विपणन नेटवर्क के माध्यम से झारखंड के पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार में राज्य सरकार के साथ साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे राज्य की पर्यटन क्षमता को व्यापक पहचान मिल सके।

ईजमाइट्रिप » ईजमाइट्रिप के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड सरकार के साथ पर्यटन संवर्धन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। कंपनी ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए प्रमुख ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स एवं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को झारखंड लाने की योजना साझा की। मुख्यमंत्री ने इस पहल का स्वागत करते हुए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन: एआई आधारित सुशासन-डिजिटल नवाचार से राज्य को अग्रणी बनाने की पेशकश

एआई स्टेट बनने को झारखंड सरकार ने पेश किया रोडमैप

रांची/नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दूसरे दिन गुरुवार को झारखंड सरकार ने एआई राज्य बनने के लिए रोडमैप पेश किया। डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से रोडमैप प्रस्तुत किया। राज्य सरकार के इस विजन का उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं नागरिक सेवाओं में एआई का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। ताकि पारदर्शी, त्वरित, जवाबदेह एवं डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित हो, जिससे आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी एवं सुलभ सरकारी सेवाएं मिल सकें।

राज्य सरकार ने प्रस्तावित झारखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति 2026-2031 की रूपरेखा पेश की। इससे शासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, खनन, पर्यावरण संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान विकसित किए जाएंगे। साथ ही डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जिम्मेदार तकनीकी उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सुशासन को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (सीएम-डीआईपी) स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।

यह एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विभिन्न सरकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं तथा विभागीय कार्यों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगी। साथ ही बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप आधारित नागरिक सेवाएं, डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली तथा पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की योजना भी पेश की गई।

नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दूसरे दिन गुरुवार को संबोधित करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और साथ में मौजूद झारखंड के मंत्री व अधिकारी। ● हिन्दुस्तान

डिजिटल विकास की घोषणा

राज्य सरकार ने दीर्घकालिक डिजिटल विकास की दिशा में स्टेट एआई मिशन, झारखंड एआई क्लाउड, एआई इनोवेशन हब, एआई पार्क, एआई इनोवेशन जोन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा समेकित स्टार्टअप एवं स्किलिंग इकोसिस्टम विकसित करने की घोषणा की।

घोषणा क्यों
इन पहलों के माध्यम से अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

तीन प्रमुख एआई पहल पर विशेष रहा जोर

- मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (सीएम-डीआईपी)
- हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (एचएनवीएस)
- क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (सीएमएएस)

जोर क्यों: इनसे शासन, स्वास्थ्य सेवाओं एवं खनिज प्रशासन को आधुनिक डेटा विश्लेषण तथा एआई के माध्यम से और अधिक सशक्त-प्रभावी बनाया जाएगा।

रोडमैप में प्रस्ताव पेश

- डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए राज्य सरकार आगामी पांच वर्षों में ₹1,150 करोड़ निवेश करेगी। यह एआई अवसंरचना के विकास, डिजिटल क्षमताओं के विस्तार, नवाचार को प्रोत्साहन तथा विभिन्न विभागों में एआई के प्रभावी उपयोग पर केंद्रित होगा।
- रांची में 100.97 एकड़ में आईटी पार्क बनेगा। इसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स एवं नवाचार आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- विजन-2050 के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य ₹10,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करना। 50 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना, 1,000 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना तथा एक लाख से अधिक एआई आधारित रोजगार पैदा करना।

लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप व समयबद्ध कार्यान्वयन

राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार शॉर्ट-टर्म योजनाओं के बजाय 'लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप' पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए।

संवाद की कमी को दूर करने का प्रयास: सीएम ने स्वीकार किया कि अतीत में बेहतर कम्युनिकेशन की कमी के कारण झारखंड की क्षमताएं दुनिया के सामने पूरी तरह नहीं आ पाईं। सरकार अब इस गैप को खत्म कर देश-विदेश के निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगी। सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, केंद्रीय मंत्रियों, तकनीकी विशेषज्ञों और निवेशकों का आभार व्यक्त करते हुए 'जोहार' के साथ अपने संबोधन का समापन किया और झारखंड के विकास में सहभागी बनने का आमंत्रण दिया।

राज्य में नवाचार एवं शोध के संस्थानों का स्वागत: मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य में नवाचार एवं शोध के संस्थानों का स्वागत है।

सियासत 30S

नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दूसरे दिन गुरुवार को मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह। ● हिन्दुस्तान

झारखंड में अवसरों का नया युग: दीपिका

रांची। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि झारखंड में अवसरों का नया युग! राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के माध्यम से झारखंड को विजन 2050 की दिशा में आगे बढ़ाने की मजबूत पहल की गई है। बड़े निवेश, आधुनिक उद्योग, तकनीकी नवाचार और विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना के साथ राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह पहल सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, समृद्ध और भविष्य के झारखंड के निर्माण की है-जहां प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

स्वास्थ्य विभाग गूगल के साथ करेगा एमओयू

रांची। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बयान जारी कर नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन को झारखंड के लिए ऐतिहासिक बताया है। कार्यक्रम के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही गूगल से एमओयू करेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति आएगी। झारखंड के सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इरफान ने कहा कि कार्यक्रम में आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कई राष्ट्रीय एवं वैश्विक कंपनियों ने झारखंड में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है।

87 हजार करोड़ का एमओयू सराहनीय: राजद

रांची। प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की सराहना की है। इसे राज्य की जनता के प्रति प्रतिबद्ध सरकार बताया। प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि सीएम ने देश के प्रमुख निवेशकों के साथ लगभग 87 हजार करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर कर राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी है। इससे जाहिर होता है कि निवेशकों ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर भरोसा जताया है।

भाजपा के आरोप राजनीति से प्रेरित: कांग्रेस

रांची। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने भाजपा प्रवक्ता संदीप वर्मा के बयान को तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पलटवार किया। उन्होंने दिल्ली में हुए स्टेकहोल्डर्स मीट को निवेश और रोजगार के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। वित्त मंत्री की अनुपस्थिति पर उठे सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकारी व्यस्तताओं के चलते किसी एक व्यक्ति की गैरमौजूदगी को बैठक की विफलता बताना उचित नहीं है।

स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन दूरदर्शी पहल: राजेश

रांची। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि पर्यटन, उद्योग और आईटी क्षेत्र में विशेषज्ञों, निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं के साथ संवाद स्वागत योग्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं। कंसल्टेशन तभी पूरी तरह सफल माना जाएगा, जब इसमें मिले सुझावों को समयबद्ध कार्ययोजना से धरातल पर उतारा जाए।

नई औद्योगिक नीतियों पर चैम्बर ने दिए सुझाव

रांची। झारखंड सरकार की ओर से नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में झारखंड चैंबर का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अगुवाई में शामिल हुआ। कार्यक्रम में झारखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 (ड्राफ्ट), टेक्सटाइल, अपैरल व फुटवियर नीति-2026 सहित विभिन्न सेक्टोरल नीतियों पर उद्यमियों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए।

झारखंड की होम स्टे नीति बनेगी नजीर : सुदिव्य

रांची/नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दूसरे दिन गुरुवार को झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड भी अब तेज विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

झारखंड देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने खनन पर्यटन (माइनिंग टूरिज्म) की पहल की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 100 होम स्टे बनाने की दिशा में काम करने जा रही है। यह रोजगार के लिए बड़ा कदम साबित होगा। राज्य सरकार की होम स्टे नीति आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों के समक्ष बड़ा उदाहरण बनेगी। कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से मंत्री ने आग्रह किया कि वे झारखंड में पर्यटन की संभावनाओं का आकलन कर अपने सुझाव दें। निवेश की दिशा में पहल करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उद्योग जगत से मिलने वाले सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी और उन्हें नीति निर्माण में शामिल करने का प्रयास करेगी।

राज्य में समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा : शिल्पी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए कहा कि राज्य सरकार झारखंड को पर्यटन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शी नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य में निवेश, रोजगार और समग्र विकास के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी। कार्यक्रम में झारखंड सरकार की प्रस्तावित नई टूरिज्म पॉलिसी एवं होम स्टे पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा की गई।

14 एमओयू पर हस्ताक्षर, 99,639 करोड़ के निवेश के गवाह

अम्बिशस सीमेंट

टाटा स्टील लिमिटेड

अंबुजा सीमेंट

गूगल एलएलसी

अमलगम स्टील

ईजमाइट्रिप

जिंदल रिन्युएबल

एमओयू झारखंड और जिंदल समूह को नई दिशा देगा: नवीन

रांची। जिंदल स्टील के अध्यक्ष नवीन जिंदल ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि वह विदेश में होने के कारण एमओयू के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रह सके। एमओयू झारखंड सरकार और जिंदल समूह के बीच साझेदारी को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड की असली ताकत प्राकृतिक संसाधन और यहां के लोग हैं। जिंदल समूह ने झारखंड में स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 70 हजार करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है।

स्टील के क्षेत्र में 10 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे

स्टील के क्षेत्र में 40 हजार करोड़ के निवेश से 10 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी। परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 30 हजार करोड़ का निवेश की भी योजना है।

झारखंड की लंबी छलांग

- राज्य सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी सचिव पूजा सिंघल, उद्योग सचिव अरवा राजकमल और पर्यटन सचिव मुकेश कुमार आदि ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
- गूगल क्लाउड और वाधवानी ग्रुप के साथ प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के विस्तार और ई-गवर्नेंस पहलों को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक समझौते किए गए।
- मेसर्स टाटा मोटर्स के साथ 'माइनिंग टूरिज्म' और ईजमाइट्रिप प्लानर्स के साथ पर्यटन संवर्धन के लिए रणनीतिक साझेदारी।
- जिंदल स्टील लिमिटेड द्वारा ₹40,000 करोड़ और मेसर्स जिंदल न्यूक्लियर पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹30,000 करोड़ के निवेश समझौते।
- झारखंड के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और शासन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी दिग्गजों के साथ रणनीतिक साझेदारी।

झूठे सपने दिखा ठगना बंद करे सरकार : भाजपा

रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि सरकार झारखंड की जनता को झूठे सपने दिखाकर ठगना बंद करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया, लेकिन लाखों युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया गया, लेकिन प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। अब सरकार नए उद्योगों और निवेश का सपना दिखा रही है, जबकि धरातल पर इसकी तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है।

वर्मा ने कहा कि निवेश संबंधी इस स्टेक होल्डर मीट में दूसरे विभागों के मंत्री उपस्थित दिखे, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिल्ली में रहते इस महत्वपूर्ण बैठक से दूर रहकर इसकी गंभीरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इससे भी ये प्रतीत होता है होटल ताज की ये मीट सिर्फ यहां के लोगों के साथ छलावा है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

ROSARB राँची
तृतीय तल, एल एम स्क्वायर, सुजाता चौक, मेन रोड, राँची - 834001, झारखंड

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संगठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम- 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय का ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणी(यों), बंधककर्ता(ों) तथा जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित बंधक / प्रभारित अचल संपत्ति प्रतिभूत ऋणदाता के कब्जे में है, जिसका **"जहाँ है, जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणकर्ताओं / बंधककर्ता / जमानतदार / सुरक्षित संपत्ति / बकाया राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नवर्णित है :

क्र. सं.	ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें ज्ञात अदिभार (यदि कोई हो) भी शामिल है	कुल बकाया राशि/ ई-नीलामी की तिथि/ ई-नीलामी का समय	आरक्षित मुल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय
01	**मेसर्स संचार नेटवर्क** **प्रोप्राइटर: श्री राकेश कुमार गुप्ता,** द्वितीय तल, गौरव टॉवर, मानगो चौक, मानगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम - 831012 **जमानतदार / बंधककर्ता :** **श्रीमती भागीरथी देवी,** पति - स्वर्गीय सूरज प्रसाद गुप्ता, 58C, टीचर्स कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम - 831012	भूमि एवं भवन का समतुल्य बंधक, जो कि पुराने प्लॉट संख्या 156, पुराना खाता संख्या 7, प्लॉट संख्या 2339, खाता संख्या 437, थाना संख्या 1642, वार्ड संख्या 10 में स्थित है, जिसमें कुल 4.95 डिसमिल में से 2.52 डिसमिल (0-3-4 धुर) भूमि सम्मिलित है, मौजा - मानगो, टीचर्स कॉलोनी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में श्रीमती भागीरथी देवी, पति - सूरज प्रसाद गुप्ता के नाम पर अवस्थित है। **सीमाएँ (वास्तविक) :** उत्तर - विक्रेता निज (उसी भूमि का शेष विक्रय भाग), दक्षिण - डी. गौड़, पूर्व - 12 फीट रोड, पश्चिम - बंगाली बाबू	**₹ 2,05,85,232.42** + दिनांक 28.09.2021 से मांग सूचना के अनुसार अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार सहित तथा संविदात्मक देय राशि दिनांक 31.12.2025 को ₹ 3,43,53,413.08 है, इसके अतिरिक्त लागत एवं ब्याज देय होगा। **06.08.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 37,03,000/- रु. 3,70,300/- रु. 10,000/-	**सांकेतिक कब्जा** **25.07.2026 से 05.08.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 04:00 बजे तक**

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल **https://baanknet.com** देखें।
इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर **7542032124** पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : राँची
दिनांक: 09.07.2026

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

ह0/- प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा, ROSARB राँची

जीरो कोल लीकेज | अमित शाह के आदेश पर एक्शन, सीआईएसएफ ने चलाया अभियान, कोयलाा तस्करों में हड़कंप

झारखंड-बंगाल में बड़ी कार्रवाई, 428 टन कोयला जब्त

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर शुरू हुई जीरो कोल लीकेज (कोयले की शून्य चोरी) मुहिम के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। एमएमडीआर एक्ट के तहत मिली नई शक्तियों का उपयोग करते हुए सीआईएसएफ ने पिछले चार दिनों (चार-आठ जुलाई) के भीतर भारी मात्रा में अवैध कोयला और वाहन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। सीआईएसएफ से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोल इंडिया की सहायक कंपनियों- बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल के क्षेत्रों में संयुक्त छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 428.34 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया गया। चार एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही कोयले के अवैध परिवहन और खनन में इस्तेमाल एक हाइवा, 13 से अधिक मोटरसाइकिलें और कई अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

धनबाद में ड्रोन से निगरानी, 319 टन कोयला जब्त

अवध कायला कारोबार क खिलाफ सबस बड़ा कामयाबा धनबाद क बीसीसीएल क्षेत्र में मिली। सीआईएसएफ ने कतरास, ब्लॉक-2, बसंतीमाता (कारगिल), कुस्तौर, सिजुआ, जियलगोरा, बरोरा, गोविंदपुर और एनटीएसटी इलाकों में सटीक खुफिया इनपुट और ड्रोन निगरानी के जरिए छापेमारी की। यहां से 319.54 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया गया। साथ ही कोयले से लदा एक ट्रक और दर्जनों मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं।

ईसीएल और सीसीएल क्षेत्रों में भी शिकंजा: ईसीएल सीतलपुर, राजमहल, सालानपुर, चित्रा, चापापुर और सोनपुर-बाज़ारी जैसे क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाकर 85.93 मीट्रिक टन अवैध कोयला जब्त किया गया। इस दौरान इस दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सीआईएसएफ ने कोयला डिपो, धर्मकांटों और उत्पादन रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की। सीसीएल पिपरवार व करगली में रूटीन चेकिंग के दौरान 13.62 मीट्रिक टन अवैध कोयले से लदा एक हाइवा ट्रक पकड़ा गया। वहीं, करगली क्षेत्र में विशेष ऑपरेशन चलाकर 9.25 मीट्रिक टन कोयला और 7 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं।

हाईटेक तकनीक से कसी जा रही नकेल

सीआईएसएफ ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए मानव खुफिया तंत्र के साथ-साथ ड्रोन सर्विलांस, जीपीएस आधारित दस्तावेज़ीकरण और औचक निरीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। सीआईएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय खनिज संसाधनों की सुरक्षा और कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह विशेष अभियान आगे भी पूरी कड़ाई से जारी रहेगा। अवैध खनन, परिवहन या भंडारण में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।